CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

टीटीडी के साहीवाल गाय प्रजनन कार्यक्रम के लिए केंद्र ने 40 करोड़ रुपये का अनुदान दिया

केंद्र सरकार ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को उनके साहीवाल गाय प्रजनन कार्यक्रम में समर्थन देने के लिए 40 करोड़ रुपये का पर्याप्त अनुदान आवंटित किया है। यह घोषणा टीटीडी के अध्यक्ष भुमना करुणाकर रेड्डी ने एस वी गोसंरक्षणशाला में एक गाय पूजा कार्यक्रम के दौरान की।

रेड्डी ने हिंदू संस्कृति में गायों की पवित्र स्थिति पर जोर देते हुए टीटीडी के साहीवाल गाय प्रजनन कार्यक्रम को सरकार की मान्यता के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने भारत के सभी नागरिकों से पूजनीय "गोमाता" या गाय माता की रक्षा करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अनुसार, अपनी असाधारण दूध उत्पादन क्षमताओं के लिए जानी जाने वाली साहीवाल गाय को भारत की प्रमुख दुधारू पशु नस्लों में से एक माना जाता है।

इसके अलावा, रेड्डी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एस वी गौशाला में गाय पूजा कार्यक्रम एक वार्षिक परंपरा है, और टीटीडी, जो कि तिरूपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर का आधिकारिक संरक्षक है, ने किसानों को मवेशी दान करने सहित विभिन्न गाय संरक्षण पहल की है। यह अनुदान भारत की समृद्ध कृषि विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

दूध परिवहन और परीक्षण वाहन डेयरी सहकारी समितियों को सौंपे गए

एक महत्वपूर्ण विकास में, डेयरी विकास निदेशालय ने राज्य में 18 डेयरी सहकारी समितियों को "दूध परिवहन और परीक्षण वाहन (एनपीडीडी के तहत)" वितरित किए। हैंडओवर समारोह शिलांग के माविओंग में सेंट्रल डेयरी परिसर में हुआ और इसमें पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री, ए.एल. हेक की उपस्थिति थी।

मंत्री हेक ने सभा को संबोधित करते हुए स्वीकार किया कि राज्य में डेयरी खेती अभी भी शुरुआती चरण में है। उन्होंने निवासियों से डेयरी उत्पाद उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता पर जोर देते हुए डेयरी फार्मिंग में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। इसके अलावा, उन्होंने उत्पादन को अधिकतम करने और विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निजी क्षेत्र और सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, मंत्री हेक ने व्यक्तिगत रूप से डेयरी सहकारी समितियों को चाबियाँ सौंपी और नए अधिग्रहीत वाहनों को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई। यह पहल राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एफएसएसएआई ने संदर्भ के रूप में मान्यता प्राप्त 11 प्रयोगशालाओं की अद्यतन सूची जारी की

खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना) विनियम, 2018 के विनियमन 3 के तहत, एफएसएसएआई ने विशिष्ट क्षेत्रों के लिए इन खाद्य प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं (एनआरएल) के रूप में मंजूरी दे दी है। इस सूची में आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों के लिए कोचीन में निर्यात निरीक्षण एजेंसी, स्वास्थ्य पूरक और पोषण संबंधी जानकारी के लिए मैसूर में सीएसआईआर-केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, और कीटनाशकों और माइकोटॉक्सिन के लिए पुणे में आईसीएआर-राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र जैसी प्रयोगशालाएं शामिल हैं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 'संदर्भ प्रयोगशालाएँ' के रूप में नामित 11 प्रयोगशालाओं की एक अद्यतन सूची जारी की है। यह फैसला इस साल जून में उनकी मान्यता खत्म होने के बाद आया है. एफएसएसएआई इन प्रयोगशालाओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है।

ये एनआरएल प्रमाणित संदर्भ सामग्री, मानक विकास और तकनीकी सहायता के लिए संसाधन केंद्र के रूप में काम करेंगे।

मध्य प्रदेश: पिछले 15 दिनों में लम्पी वायरस के मामलों में गिरावट

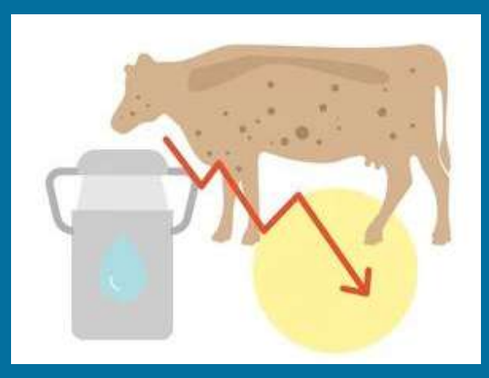

एक सकारात्मक घटनाक्रम में, मध्य प्रदेश राज्य में पिछले 15 दिनों में मवेशियों में गांठदार त्वचा रोग (एलएसडी) के मामलों में गिरावट देखी गई है, जो दर्शाता है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। दैनिक निगरानी और निवारक उपायों ने इस सुधार में योगदान दिया है। अब तक, राज्य में उल्लेखनीय रूप से 51,10,864 जानवरों को एलएसडी के खिलाफ निवारक टीकाकरण प्राप्त हुआ है। एलएसडी वैक्सीन और दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति के साथ, अधिकारी संदिग्ध जानवरों को उपचार प्रदान करना जारी रखते हैं।

विशेष रूप से, भोपाल जिले में 25 अगस्त, 2023 को पहला एलएसडी मामला दर्ज किया गया था, जिसकी पुष्टि 31 अगस्त को राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा प्रयोगशाला द्वारा की गई थी। पिछले महीने जिले में प्रभावित 43 जानवरों में से, 35 ने ठीक होने के संकेत दिखाए हैं, जबकि 8 हैं फिलहाल इलाज चल रहा है. संक्रमित जानवरों को 'आसरा' पशु आश्रय में अलग रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है, और भोपाल नगर निगम संदिग्ध मामलों के लिए नबी बाग में कांजी हाउस में एक संगरोध केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहा है।

भोपाल जिले में कुल 1.24 लाख गोवंश के साथ, चल रहे प्रयासों में आगे के प्रकोप को रोकने के लिए जानवरों का टीकाकरण करना शामिल है। एलएसडी का प्रकोप शुरू में मई में बालाघाट जिले में शुरू हुआ, और वर्तमान में राज्य के दो जिलों को प्रभावित करता है, पिछले चार महीनों में 9,446 जानवर प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 9,323 सफलतापूर्वक ठीक हो गए हैं।

जम्मू और कश्मीर में डेयरी प्रौद्योगिकी की क्षमता को उजागर करना

भारत में डेयरी क्षेत्र ग्रामीण विकास और आर्थिक विकास की आधारशिला रहा है, जो देश की आत्मनिर्भरता और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 23% हिस्सा है। यह संपन्न उद्योग भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लाखों परिवारों को आय सृजन और पोषण के महत्वपूर्ण स्रोत दोनों के साथ सशक्त बनाता है।

डेयरी क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास निधि (एएचआईडीएफ), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा शामिल हैं। विकास निधि (डीआईडीएफ), पशुपालन और डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), और डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस)।

पशुधन उत्पादकता को बढ़ावा देने की सरकारी पहल के उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं, दूध उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। 2020-21 और 2021-22 में, भारत ने क्रमशः 209.96 मिलियन और 221.06 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया, जो 5.29% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। 2021-22 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता लगभग 444 ग्राम प्रतिदिन है।

विशाल और मुख्य रूप से महिला ग्रामीण कार्यबल के साथ, डेयरी उद्योग रोजगार सृजन में एक प्रमुख खिलाड़ी है। जैसे-जैसे दूध की मांग बढ़ती जा रही है, वृद्धि और विकास के अवसर प्रचुर मात्रा में हैं। नीति आयोग का अनुमान है कि 2033-34 तक भारत का दूध उत्पादन 330 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा, जिससे संभावित रूप से भारत वैश्विक दूध उत्पादन का 33% का स्रोत बन जाएगा।

इस परिदृश्य में, डेयरी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और कुशल कार्यबल का निर्माण करना इस क्षेत्र की निरंतर सफलता के लिए आवश्यक है। खेत से लेकर कांटे तक, डेयरी आपूर्ति श्रृंखला के हर पहलू को गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। भारत के लिए अपनी डेयरी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए प्रसंस्करण, नवाचार और मानव संसाधनों में निवेश करना महत्वपूर्ण होगा।

भारत की दिल्ली में अखिल भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान (AIIVS) स्थापित करने की योजना है

भारत सरकार प्रसिद्ध अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के नक्शेकदम पर चलते हुए, पशु स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित एक अभूतपूर्व संस्थान बनाने के लिए तैयार है। प्रस्तावित अखिल भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान (AIIVS) उत्कृष्टता का एक राष्ट्रीय केंद्र बन जाएगा, जो जानवरों, बाह्य रोगी और आंतरिक रोगी चिकित्सा सेवाओं के लिए 200-500 सीटर अल्ट्रा-आधुनिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की पेशकश करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के भीतर उपयुक्त भूमि की तलाश चल रही है, जिससे एआईआईवीएस को आसान पहुंच मिल सके और इसे भारत का शीर्ष पशु चिकित्सा रेफरल अस्पताल बनाया जा सके। इसमें साथी जानवरों, खेत जानवरों, घोड़ों, वन्य जीवन और विदेशी पालतू जानवरों के लिए विशेष विभाग शामिल होंगे।

AIIVS का लक्ष्य स्नातक पशु चिकित्सकों के लिए उन्नत निदान और शिक्षण सुविधाएं प्रदान करके पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों को ऊंचा उठाना है। यह स्नातकोत्तर और पीएचडी के लिए एक नवाचार और अनुसंधान केंद्र के रूप में भी काम करेगा। विद्वान, सभी एक ही परिसर में।

AIIVS की स्थापना भारत में पशु कल्याण, वन्यजीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है, जो देश को वैश्विक मानकों के करीब लाती है। यह महत्वाकांक्षी प्रयास भारत के जानवरों के लिए एक उज्जवल, अधिक दयालु भविष्य का वादा करता है।

यूपी सरकार ने नंद बाबा दूध को लागू करने के लिए समिति बनाई

उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादकों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना और राज्य के डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ, मिशन राज्य भर के गांवों में दूध समितियों की स्थापना पर केंद्रित है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादकों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना और राज्य के डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ, मिशन राज्य भर के गांवों में दूध समितियों की स्थापना पर केंद्रित है।

मिशन के सुचारू संचालन की सुविधा के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक राज्य संचालन समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, डेयरी विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य कार्यकारी समिति और जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में जिला कार्यकारी समितियाँ स्थापित की गई हैं।

नंद बाबा दूध मिशन में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना और प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना सहित महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं।

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का लक्ष्य शुरुआती चरण में पशुपालकों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना राज्य में देशी नस्ल की मवेशियों की खरीद को प्रोत्साहित करती है, रोजगार के अवसर पैदा करती है और पशुपालन को बढ़ाती है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य देशी गाय की नस्लों में सुधार करना और दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है। प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसमें प्रति गाय 10,000 रुपये से 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि होगी।

"सीईडीएसआई द्वारा हेरिटेज फूड्स लिमिटेड के फील्ड पदाधिकारियों के लिए दो दिवसीय अपस्किलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम"

हेरिटेज फूड्स लिमिटेड के फील्ड पदाधिकारियों के लिए 5 से 6 सितंबर, 2023 तक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (सीईडीएसआई) द्वारा 2 दिवसीय अपस्किलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दूध खरीद और इनपुट पर्यवेक्षक की भूमिका में क्षेत्र पदाधिकारी। इस अपस्किलिंग कार्यक्रम में कुल 47 प्रतिभागी सक्रिय रूप से शामिल हुए, जिसे दूध की गुणवत्ता परीक्षण, स्वच्छ दूध प्रबंधन और पशु स्वास्थ्य प्रबंधन सहित दूध खरीद के विभिन्न पहलुओं में उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। इस पहल से हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को काफी फायदा हुआ।

हम कौन हैं?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) के तत्वावधान में काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था "भारत में डेयरी कौशल के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CEDSI)", किसानों की आजीविका के सशक्तिकरण और बेहतरी में मदद करने के लिए, वेतनभोगी कर्मचारी, और डेयरी मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारक।

सीईडीएसआई सदस्यता उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों, डेयरी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को डेयरी उद्योग के लिए आसन्न महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी।

Centre of Excellence for Dairy Skills in India

Join Our Membership Drive and Get Benefits of

- Platform to interact with other members in the sector
- Networking opportunities with corporate leaders and government authorities
- Special costs of training in Skill India Certified Programmes
- Access to our Journal and Publications
- Expert advice in day-to-day operations and management of livestock /farm productions
- Free registration on the job portal and regular updates on job vacancies in the sector
- Recognize your organization with CEDSI Yearly Awards and Recognition
- Chance to reach across the board through advertising in our press releases, news and articles
- Consultative and advisory services to help members
- Consulting and advisory services to help members
- Periodic e-newsletter for the latest news, govt. announcement and schemes in dairy sectors
- Updates on training programs of CEDSI and access to the training calendar

Who Can Become a Member -

www.cedsi.in @cedsi_india

CEDSI : रविविंग स्किल्स एंड जनरेटिंग लाइवलीहुड

किसानों/छात्रों/उद्यमियों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- डेयरी किसान / उद्यमी
- डेयरी फार्म पर्यवेक्षक
- डेयरी कार्यकर्ता
- पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन
- पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक
- पशु चिकित्सा नैदानिक सहायक
- बछड़ा पालन
- कृषि उपकरण तकनीशियन
- डेयरी फार्म अर्थशास्त्र और प्रबंधन
- उद्योग संरेखित प्रमाणन कार्यक्रम (बेरोजगार युवा और छात्र)

एफपीओ उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

- उत्पाद प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं पर एफपीओ सदस्य अभिविन्यास।
- एफपीओ मार्केट लिंकेज
- एफपीओ शासन
- एफपीओ लेखा

डेयरी कॉरपोरेट्स और सहकारी समितियों के लिए प्रमुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- चिलिंग प्लांट तकनीशियन
- बल्क मिल्क कूलर ऑपरेटर
- ग्राम स्तरीय दुग्ध संग्रह केन्द्र पर्यवेक्षक
- दूध परीक्षक
- ग्रीन हाउस गैसों का शमन
- दूध की गुणवत्ता आश्वासन
- मिल्क डिलीवरी बॉय
- दूध खरीद और इनपुट पर्यवेक्षक
- डेयरी उद्योग में अपशिष्ट प्रबंधन
- चारा और चारा प्रबंधन
- स्वच्छ दूध उत्पादन
- निर्णय समर्थन प्रणाली / डेटा विश्लेषिकी

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया